मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 68 | अप्रैल, 2023 | अंक 04 | कुल पृष्ठ 6

विश्व की डेयरी बन सकता है भारत

डॉ. आरएस सोढ़ी, (प्रेसिडेंट, इंडियन डेयरी एसोसिएशन)

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले चार-पांच दशकों से निरंतर विकास कर रही है। इसका कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दुनिया ने भी भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन 1947 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। देश औपनिवेशिक जंजीरों से तो मुक्त हो गया था लेकिन सच्चे अर्थों में आर्थिक स्वतंत्रता और खाद्य सुरक्षा हासिल करना बाकी था। आजादी के बाद हमारा पूरा फोकस देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, क्योंकि उस समय भारत विकसित देशों की तरफ से मिलने वाली खाद्य सहायता पर निर्भर था।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आणंद में संभावनाओं की तलाश की और आगे चलकर डॉ वर्गीज कुरियन के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का ढांचा तैयार हुआ। यह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की निगरानी में बना था। इस बोर्ड ने ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक क्रांति ला दी और 'अरब लीटर' के विचार को अमली जामा पहनाया। उसी का नतीजा है कि विश्व के दुग्ध क्षेत्र में भारत आज शीर्ष देशों में शामिल है। ऑपरेशन फ्लड के तहत दुग्ध कोऑपरेटिव के अमूल मॉडल को पूरे देश में अपनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन के चलते सिस्टम से बिचौलियों को हटाने में कामयाबी मिली और यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी वैल्यू चेन पर किसानों का नियंत्रण रहे। यह श्वेत क्रांति पूरी तरह से भारत के दूरदर्शी लोगों के विचारों का परिणाम थी, जबकि हरित क्रांति को पश्चिम से उधार लिया गया था।

आज भारत का डेरी और पशुपालन क्षेत्र 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए आय का मुख्य साधन बन गया है। इसने खास तौर से सीमांत और महिला किसानों को रोजगार तथा टिकाऊ आजीविका का साधन मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि अर्थव्यवस्था में डेरी और पशुपालन का हिस्सा करीब 30% है। डेयरी क्षेत्र इकोनॉमी में 9.6 लाख करोड रुपए का योगदान करता है जबकि पोल्ट्री, फिशरीज और अन्य संबंधित क्षेत्रों का योगदान तीन लाख करोड़ रुपए है। देश में हर साल जितने दूध का उत्पादन होता है उसका मूल्य गेहूं, धान

और दालों के कुल मूल्य से भी ज्यादा है। इस तरह देसी बिजनेस मॉडल को अपनाते हुए भारत ने डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल की है।

भारत के डेयरी क्षेत्र की विशाल सफलता के पीछे दो दर्शन माने जा सकते हैं-

वैल्यू फॉर मेनी: मतलब हमारे किसानों ने जितना दूध निकाला उसकी उन्हें अधिकतम कीमत मिली। उपभोक्ता दूध के लिए जितना पैसा देता है उसका 70 से 80% किसानों को मिलता है। इसके विपरीत अमेरिका और यहां तक कि यूरोप के देशों में भी किसानों को 35 से 40 फ़ीसदी हिस्सा ही मिलता है।

वैल्यू फॉर मनी: भारत का डेयरी सेक्टर इतना आगे बढ़ा तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है यह भी है कि यहां के मध्य वर्ग को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम कीमत पर मिले।

डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव की मौजूदगी से उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोऑपरेटिव ने ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिन्हें निजी क्षेत्र हासिल करने की कोशिश करता रहता है। आर्थिक पहलू के अलावा भारत का डेयरी उद्योग एक सक्षम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और तकनीकी इंटीग्रेशन का भी सफल उदाहरण बन गया है।

भारत के डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव मॉडल कितना सक्षम और प्रभावी है यह बात आंकड़ों से साबित होती है। 1950 में जब भारत खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा था उस समय हमारा कुल दूध उत्पादन सिर्फ 1.7 करोड़ टन था।

1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ तो भारत दूध के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था, जिस तरह आज हम खाद्य तेल आयात पर निर्भर करते हैं। दूध उत्पादन 2.1 करोड़ टन पर स्थिर था और विश्व के कुल 42.5 करोड़ टन उत्पादन में भारत का हिस्सा सिर्फ 5% था। अमेरिका की तुलना में एक तिहाई और यूरोप की तुलना में आठवें हिस्से के बराबर दूध उत्पादन भारत में होता था।

ऑपरेशन फ्लड के नतीजे तब देखने को मिले जब 1997 में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। यहां सालाना 7.4 करोड़ टन दूध का उत्पादन हो रहा था। उस दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 110 ग्राम से बढ़कर 214 ग्राम हो गई थी। 1997 से लेकर आज तक भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक बना हुआ है। आज यहां 21 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है और दुनिया के 91 करोड टन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 23% पहुंच गई है। अन्य देशों से तुलना करें तो अमेरिका की तुलना में भारत का उत्पादन दोगुना और यूरोप से 30% ज्यादा है।

भारत में दूध का उत्पादन पिछले 20 वर्षों के दौरान सालाना 4.8% की दर से औसत दर से बढ़ा है, जबकि इस अवधि में दूध का वैश्विक उत्पादन 1.8% के और सबसे बढ़ा है। सच तो यह है कि दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसके 50% से ज्यादा भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशियाई देशों से आया है।

सालाना 4.6% की अनुमानित वृद्धि दर से भारत 2047 तक 63 करोड़ टन के स्तर को हासिल कर सकता है। उस समय दूध का वैश्विक उत्पादन 135 से 140 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इस तरह विश्व के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 45% होगी।

हालांकि अन्य उद्योगों की तरह डेयरी और पशुपालन उद्योग के सामने भी चुनौतियां हैं। अगले 25 वर्षों (2047 तक) में 63 करोड़ टन दूध उत्पादन के लक्ष्य को

हासिल करने के लिए भारत को तत्काल निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। 2047 तक देश में 10 करोड़ टन सरप्लस दूध उपलब्ध होगा जिससे निर्यात के काफी अवसर निकलेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के नए बाजार नहीं तलाशे गए तो किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाएगी और वह डेयरी बिज़नेस को अपनाने के प्रति हतोत्साहित होंगे।

अगले 2 वर्षों के दौरान भारत के डेयरी सेक्टर को अपनी स्थिति मजबूत करने और नई दिशाएं तलाशने की आवश्यकता है। डेयरी और पशुपालन को नई पीढ़ी के डेयरी किसानों के सामने आर्थिक रूप से मुनाफे वाले सेक्टर के रूप में रखा जाना चाहिए। देश के नेतृत्व को इस क्षेत्र की कमजोरियों के साथ संभावनाओं को भी समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे प्रमुख लक्ष्यों में एक राजनीतिक नेतृत्व और नीति निर्माताओं को इस लिहाज से संवेदनशील बनाने की जरूरत है। देश की जीडीपी में डेयरी सेक्टर जो योगदान कर रहा है उसी अनुपात में इसके लिए बजट आवंटन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें 2050 में देश के 165 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

हमारे सामने भारत को विश्व की डेयरी के रूप में स्थापित करने का मौका है। चाहे वह कोऑपरेटिव सेक्टर के कामकाज का तरीका हो, उनके मॉडल को लागू करना हो, विशेषज्ञता का इस्तेमाल हो या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अपनाने की बात हो, हमें अपने आप को इस तरह तैयार करने की जरूरत है कि विश्व डेयरी क्षेत्र में हर समाधान के लिए भारत की ओर देखे। हमारा लक्ष्य सिर्फ सबसे बड़ा उत्पादक बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत और विश्व के लोगों के लिए सेहत और पोषण भी सुनिश्चित होना चाहिए। इससे भारत के डेयरी किसान की संपन्नता की लगातार बढ़ती रहेगी।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति से ज्यादा श्वेत क्रांति का योगदान, डेयरी में निर्यात प्रतिस्पर्धी बने भारतः प्रो. रमेश चंद

श्री हरवीर सिंह, प्रधान संपादक, रूरल वॉयस

हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से ही डेयरी क्षेत्र ने फसलों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है। श्वेत क्रांति का योगदान हरित क्रांति से कहीं अधिक है। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में डॉ. कुरियन मेमोरियल भाषण देते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, "यह साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि भारत में हरित क्रांति की तुलना में श्वेत क्रांति अधिक शक्तिशाली रही है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण के बाद फसल क्षेत्र की तुलना में डेयरी क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।" कृषि क्षेत्र की कुल आय में एक चौथाई योगदान डेयरी क्षेत्र देता है। उन्होंने कहा, "देश में दूध उत्पादन सालाना 6 फीसदी से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह से आने वाले वर्षों में निर्यात के लिए दूध अधिशेष में वृद्धि होगी। भारत के डेयरी उत्पाद को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक है। हालांकि, घरेलू डेयरी उद्योग किसी भी मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करता है जिसमें डेयरी उत्पादों के व्यापार (आयात) का उदारीकरण शामिल है।"

उनके मुताबिक, अगर हमें भविष्य में सरप्लस दूध

को खपाने के लिए विदेशी बाजारों में पैठ बढ़ानी है तो हमें निर्यात प्रतिस्पर्धी होना पड़ेगा। कोई भी देश तब तक निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता है जब तक वह आयात से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ न हो। यह मुद्दा डेयरी उद्योग के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

कृषि क्षेत्र की कुल आय (2006-07 से 2020-21) में डेयरी क्षेत्र की हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सामने दो प्रमुख चुनौतियां थीं। पहला, दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता और दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिसका जलवायु परिवर्तन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डेयरी क्षेत्र की एक और आलोचना इस बात को लेकर होती है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान डेयरी पशुओं की आबादी बढ़ी है जिसकी वजह से दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पशुओं की आबादी बढ़ने का गंभीर पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रभाव होता है। दूसरी ओर, देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत पिछले 20 वर्षों के दौरान बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि खपत में इस वृद्धि का मतलब यह है कि दूध ने देश के पोषण में सुधार में काफी बड़ा योगदान दिया है।

प्रो. रमेश चंद ने बताया कि भारत में डेयरी क्रांति की सफलता को निर्यात से जोड़कर नहीं बताया गया है। एपीडा द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिखाया गया है कि डेयरी निर्यात कृषि निर्यात का केवल 2.6 फीसदी है जो कुल हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है। फसल और पशुधन उत्पादन के मूल्य में दूध उत्पादन की हिस्सेदारी 24 फीसदी है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 2017-18 के बाद चार वर्षों में डेयरी उत्पादों के निर्यात की मात्रा चार गुना बढ़ गई है। 2021-22 में डेयरी निर्यात दोगुना होकर 2,742 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि मात्रा में 64 फीसदी की वृद्धि हुई है।

भारत के कृषि विकास का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए प्रो. चंद ने कहा, "यदि पिछले 50 वर्षों में कृषि के विकास को देखा जाए तो हरित क्रांति का हिस्सा 13.23 फीसदी है लेकिन दूध का योगदान 25 फीसदी है। इसका मतलब यह है कि कृषि के विकास में श्वेत क्रांति का योगदान हरित क्रांति की तुलना में दोगुना है। वहीं पिछले 50 वर्षों में पॉल्ट्री क्षेत्र का योगदान देश की शीर्ष फसल गेहूं के मुकाबले अधिक है। कृषि विकास में पॉल्ट्री का योगदान 6.3 फीसदी है। इसी तरह मत्स्य पालन का योगदान 7.8 फीसदी है जो किसी एक फसल के योगदान की तुलना में कहीं अधिक है। विकास के इस अंतर ने कृषि क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल दी है। फसल क्षेत्र का हिस्सा सिकुड़ रहा है, जबकि पशुधन और डेयरी का हिस्सा बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। ये परिवर्तन विविधीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं जो कृषि में हुआ है।" उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फसल क्षेत्र को समर्थन या सब्सिडी नहीं दिया होता तो विविधीकरण और अधिक होता। पिछले 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन दोगुना होने के बावजूद कुपोषण और एनीमिया की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "1971 से 2021 के बीच 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति कुल खाद्य उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। इनमें अनाज, खाद्य तेल, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडा, चीनी सहित नौ खाद्य पदार्थ शामिल हैं। 1971 में भारत प्रति व्यक्ति रोजाना एक किलोग्राम खाद्य उत्पादन कर रहा था। लेकिन अब हम प्रति व्यक्ति रोजाना दो किलोग्राम खाद्य उत्पादन कर रहे हैं। हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,

बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विकास दर हाल के वर्षों में, खासकर 2005-06 के बाद और तेज हुई है। इसके बावजूद महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया जैसे मुद्दे ज्वलंत बने हुए हैं।"

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "1979-80 में भारत की करीब 38 फीसदी आबादी कुपोषित या भूखी पाई गई थी। पांच साल पहले यह आंकड़ा घटकर 16 फीसदी रह गया था लेकिन तब से अब तक यह इसी जगह पर अटका हुआ है। जिन राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है वहां भी 50 फीसदी महिलाएं खून की कमी (एनीमिया) से पीड़ित हैं। हमें यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम पोषण में और सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य उत्पादन की विकास दर बढ़ने के बावजूद हम एनीमिया को कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं।"

पोषण में सुधार के लिए दूध एवं डेयरी उत्पादों, दालें, अंडे और मछली जैसे विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर देने का सुझाव देते हुए प्रो. चंद ने कहा, "अभी अनाज की विकास दर दो फीसदी है। यह वृद्धि दर बढ़कर अगर पांच फीसदी हो जाती है तो भी इस वृद्धि के माध्यम से भारत के पोषण में सुधार की संभावना कम ही है।"

उन्होंने कहा, "देश के दो-तिहाई लोगों को 40 फीसदी अनाज की आपूर्ति करने के बाद भी कुपोषित आबादी के प्रतिशत में सुधार नहीं हो रहा है। यदि हम पोषण में सुधार करना चाहते हैं तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने होंगे जिनका लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमें डेयरी, दालें, फल और सब्जियां, अंडे और मछली जैसी चीजों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है।"

* * *

(भारत कृषक समाज उपर्युक्त लेखों से संबंध नहीं रखता है, यह लेखकों की निजी राय है)

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

विनम्र श्रद्धांजलि

प्रो. अरुण भीला पाटिल (महाराष्ट्र), सदस्य,
अखिल भारतीय कृषक परिषद, भारत कृषक समाज

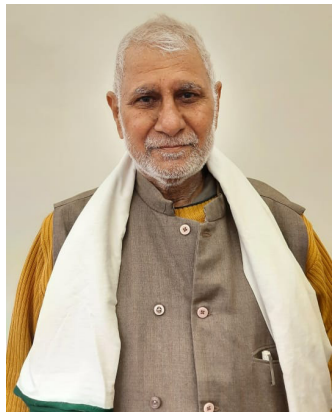

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (दिल्ली), सदस्य,
अखिल भारतीय कृषक परिषद, भारत कृषक समाज

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 अप्रैल, 2023
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, अप्रैल 2023

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**